प्रेषक.

डी०एस० गर्ब्याल, स्रविव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुमाग-2

देहरादून : दिनांक / िसितम्बर, 2016

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरपालिका परिषद, बागेश्वर को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

A STATE OF THE

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, बागेश्वर के पत्रांक—304/2016—17, दिनांक 30.08. 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, बागेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत निम्निलिखित निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार कुल ₹15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:— (धनराशि रू० लाख में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत
1.	बागनाथ वार्ड में नदी की ओर पूर्व से बने घाट में सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5.00
2.	घटबगुड वार्ड में जनमिलन केन्द्र का पुनीनिर्माण व अन्य आवश्यक कार्य।	5.00
3.	दुगबाजार वार्ड में मीट मार्केट के नीचे सुरक्षा दीवार का निर्माण।	5.00
7	ચોંગ—	15.00

2— उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही है:-

 उक्त धनराशि कुल ₹ 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, बागेश्वर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

 उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

3. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी /अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

4. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

5. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मित्रिव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

6. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

7. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

8. स्वींकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के ग्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

- 9. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं / कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

11. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

- 12. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 13. धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- 15. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 2— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—मिलन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।
- 3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/xxvII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी—S.1609130.246. के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय, / (डी०एस० गर्ब्याल) सचिव।

संख्या- 1583(1)/IV(2)-श0वि0-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
- आयुक्त, कुमांक मण्डल, नैनीताल।
- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8 निर्देशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
 - 9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 10. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बागेश्वर।
 - 11. गार्ड बुक ।